मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 4768
31 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मुद्दे

4768 श्री हेमन्त पाटिल:

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, शमन और अनुकूलन जैसे मुद्दों का समाधान किया है;
(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के संबंध में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के अंतर्गत इन मुद्दों से संबंधित ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) आज की तारीख तक चिह्नित शहरों में इन एससीएम परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें उपरोक्त मुद्दों का समाधान करने के लिए अत्यधिक ध्यान दिया गया है?

उत्तर
<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>
(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग): भारत सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) की शुरूआत की। जनवरी 2016 से जून 2018 तक प्रतियोगिता के 4 दौर के माध्यम से 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है। एससीएम का मुख्य उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मूलभूत अवसंरचना प्रदान करते हैं और 'स्मार्ट समाधानों' के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता युक्त जीवन और स्वच्छ एवं सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं।

शहर के स्तर पर एससीएम का कार्यान्वयन इस उद्देश्य के लिए बनाए गए विशेष प्रयोजन तन्त्र (एसपीवी) द्वारा किया जाता है। प्रत्येक शहर के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीपी) व्यापक नागरिक भागीदारी के माध्यम से तैयार किया गया है। चूंकि विभिन्न शहरों में नागरिकों की जरूरतें और आकांक्षाएं अलग-अलग हैं, ऐसे में एससीपी में निहित प्राथमिकताएं और परियोजनाएं भी एक शहर से दूसरे शहर में भिन्न होती हैं।

अधिकांश स्मार्ट शहरों जिनमें महाराष्ट्र के स्मार्ट शहर भी शामिल हैं, ने अपने एससीपी के भाग के रूप में जलवायु परिवर्तन, आपदा तैयारी, शमन और अनुकूलन से संबंधित मुद्दों का समाधान किया है।

पैदल चलने बढ़ावा देने के लिए, गैर-मोटर चालित और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ाने के लिए, स्मार्ट सिटीज, 4 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, 26,794 करोड़ रूपये की 789 स्मार्ट रोड परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं, गैर-मोटर चालित परिवहन और बेहतर पैदल यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप भीड़भाड़, पर्यावरण प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसें में कमी हुई हैं। इसी प्रकार, 1,301 करोड़ रूपये की 95 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। 24,029 करोड़ रूपये की 316 स्मार्ट जल परियोजनाओं और 17,983 करोड़ रूपये की 268 स्मार्ट अपशिष्ट जल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। इन और इनकी तरह की कई पहलें, जिनसे ग्रीनहाउस गैसों, प्रदूषण में कमी आगामी और संसाधन संरक्षण होगा, मिशन का हिस्सा हैं।

जलवायु स्मार्ट सिटीज आकलन ढांचे (सीएससीएएफ) को 2019 में शहरों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उनमें जलवायु-संवेदनशील विकास पद्धतियों को मजबूत बनाने के लिए एक तंत्र के रूप में शुरू किया गया था। आकलन के दूसरे संस्करण की अंतिम रिपोर्ट, सीएससीएएफ 2.0 25 जून 2021 को जारी की गई थी। 126 भाग लेने वाले शहरों का आकलन 5 विषयगत क्षेत्रों अर्थात् ऊर्जा और हरित भवन; शहरी नियोजन, हरित आवरण और जैव विविधता; गतिशीलता और वायु गुणवत्ता; जल प्रबंधन; और अपशिष्ट प्रबंधन के 28 विविध संकेतकों के माध्यम से किया गया था। सीएससीएएफ-2.0 के परिणाम https://niua.org/c-cube/c-cube-documents पर उपलब्ध हैं।

भारत के शहरों में जलवायु संबंधी कार्रवाई में सहायता करने के लिए, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) के तहत शहरों के लिए जलवायु केंद्र (सी-क्यूब) की स्थापना की गई है।

76 स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) परिचालित किए गए हैं। ये आईसीसीसी बेहतर यातायात प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल वितरण प्रबंधन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपदा प्रबंधन इनके कार्यों का एक प्रमुख घटक है। स्मार्ट शहरों ने कोविड-19 महामारी के बेहतर प्रबंधन के लिए आईसीसीसी और संबंधित स्मार्ट बुनियादी ढांचे का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है।

कोविड -19 महामारी से ग्रीन रिकवरी के महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ, एससीएम ने सुरक्षित, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल शहरों अर्थात स्ट्रीट फॉर पीपल,इंडिया साईकिल फॉर चैंज,ट्रान्सपोर्ट फॉर ऑल, नैरचरिंग नेबरहुड और ईटस्मार्ट सिटीज चैलेंज को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण चुनौतियों की शुरूआत की है।

***